खण्ड: 4, अंक: 5 मई 2021

# संश्लेषण

डी सी आर सी मासिक पत्रिका

## कोविड टीकाकरण नीति एवं राजनीति

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केंद्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

**मुख्य संपादक**
प्रो. सुनील के चौधरी

**संपादक**
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

**संपादकीय मंडल**
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2021

रूपाकंनः आर. किशोर

# संश्लेषण

## कोविड टीकाकरणः नीति एवं राजनीति

अनुक्रमिका


संपादकीय i-ii

1. कोविड टीकाकरणः नागरिकों की सुरक्षा या राजनीतिक अवसरवादिता? 1–5

– हितेन्द्र बारगल

– प्रियंका बारगल

2. कोविड टीकाकरण अभियानः निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका 6–13

– राम किशोर

3. भारत में कोविड टीकाकरण की बदलती नीति एवं बढ़ती राजनीति 14–20

– डॉ. अमित अग्रवाल

4. कोविड़ टीकाकरणः शीघ्रता, सुगमता एवं बुद्धिमत्ता – सृष्टि 21–24

5. कोरोना, टीकाकरण, मानवता एवं राजनीति – रजनी 25–29

# सम्पादकीय

विकासशील राज्य शोध केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी अकादमिक निरंतरता को अनवरत रखते हुए अपनी हिंदी मासिक पत्रिका संश्लेषण के 34वें अंक को प्रसन्नतापूर्वक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। हिंदी लेखन व पठन को समर्पित यह मासिक पत्रिका 2018 से निरंतर समसामयिक विषयों पर विभिन्न शिक्षार्थियों व शोधार्थियों द्वारा उत्कृष्ट लेखन को प्रोत्साहित कर रही है। समाज विज्ञान के विविध अनुशासनों को अपने भीतर समाहित करते हुए यह पत्रिका विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लेख आमंत्रित करती है। प्रस्तुत अंक भी इसी दिशा में किया गया एक सामूहिक प्रयास है।

कोरोना संकट ने वैश्विक स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। भारत भी इन चुनौतियों से अछूता नहीं रहा है। समाज का प्रत्येक वर्ग इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। यद्यपि भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने इसके समाधान के रूप में विकसित विषाणु रोधी टीकाकरण अभियान प्रारम्भ कर दिया है, परंतु यह अभियान प्रारम्भ से ही विविध प्रकार की चुनौतियों से घिरा रहा है। ये चुनौतियाँ कहीं नीतिगत रहीं तो कहीं राजनीति से प्रेरित।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में किसी भी नीति का कार्यान्वयन दुरूह एवं चुनौती–पूर्ण है। इस दुरूहता का एक कारण जहाँ सभी लोगों तक पहुँच बनाना है, वही दूसरी ओर केंद्र व राज्यों के मध्य सामंजस्य व समन्वय का अभाव होना भी है। ऐसे में कोविड जैसी वैश्विक महामारी से उपजे नैराश्य के बीच टीकाकरण के रूप में जो आशा की किरण दिखाई दी है, उसकी सफलता व्यक्तियों, राज्यों व सरकारों की व्यवहारिक सहजता में निहित है। भारत में जहाँ एक ओर कोविड टीकाकरण अभियान में केंद्र–राज्य संबंधों पर विमर्श को तीव्रता दी गई, वैक्सीन कूटनीति, वैक्सीन राष्ट्रवाद जैसे नवीन प्रत्ययों को जन्म दिया गया, भारत द्वारा कोविड–रोधी टीके के आयात–निर्यात संबंधी नीति को विश्लेषित किया जाने लगा, वहीं दूसरी ओर भारत द्वारा विभिन्न देशों को, मैत्रीपूर्ण संबंधों को ध्यान में रखते हुए, सहायतार्थ टीके भेजे जाने को प्रश्नांकित भी किया गया। इस संदर्भ में कोविड टीकाकरण अभियान का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है।

उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए पत्रिका का मई 2021 यह अंक कोविड टीकाकरण अभियान के विविध पक्षों को केंद्र में रखकर लिखे गए विभिन्न लेखों में से चयनित 5 उत्कृष्ट लेखों का संग्रह है। इन लेखों के माध्यम से भारत में कोविड टीकाकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों व इन प्रयासों के समक्ष आने वाली नीतिगत एवं राजनीतिक चुनौतियों को सामने रखने का प्रयास किया गया है। संपादक मंडल द्वारा चयनित ये समस्त लेख अपनी प्रकृति में सृजनात्मक एवं मौलिक हैं। इनमें व्यक्त विचार लेखकों के स्वतंत्र चिंतन को अभिव्यक्त करते हैं।

सुधी पाठकों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम पत्रिका के आगामी अंकों की गुणवत्ता में निरंतर रचनात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते रहेंगे।

संपादक मंडल

सोमवार, 19 जुलाई 2021

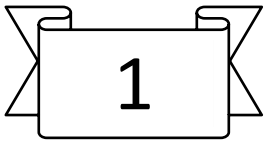


# कोविड टीकाकरणः नागरिकों की सुरक्षा या राजनीतिक अवसरवादिता?

हितेन्द्र बारगल

सहायक प्राध्यापक

शासकीय महाविद्यालय

गुनौर, जिला पन्ना, (म.प्र.), भारत

प्रियंका बारगल

शोधार्थी

अर्थशास्त्र अध्ययनशाला

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, (म.प्र.), भारत

भारत देश के लिए ही नहीं वरन सम्पूर्ण विश्व के लिए वर्ष 2019 बहुत संकटमय रहा, यही वह दुर्भाग्यपूर्ण साल था, जब कोविड–19 जैसी महामारी का पता लगा तथा कुछ समय अंतराल में ही इस महामारी ने संपूर्ण विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस महामारी से न केवल जनहानि हुई, वरन इस महामारी ने कई विकसित और विकासशील देशों की स्वास्थ्य संबंधी नीतियों की पोल भी खोल दी। कोविड–19 के कारण जहां कई गरीब देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, वहीं भारत देश ने कुशल नेतृत्व के सहारे आत्मनिर्भर होने का सपना देखा, तथा उसे पूरा करने में जुट गया ,जिसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने हैं। आज हम न केवल पीपीई किट, वैक्सीन का स्वयं उत्पादन कर रहे हैं, बल्कि हमारे पडोसी देशों की भी सहायता कर रहे हैं। आज हम टीकाकरण करने में एक रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। भारत देश की इतनी बडी जनसंख्या होने के बावजूद भी जिस तरह से टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी आई है, वह तारीफ योग्य है। वर्तमान दशा कि अगर हम बात करें , तो हमें ज्ञात होता है कि कोरोना की वजह से हमारे जीवन में बहुत उथल–पुथल तथा असमंजस की स्थिति आ गई है, इससे जीवन का हर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है घकोरोना से राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

देखा गया है, कि जिन देशों में टीकाकरण हो गया है, वहां कोविड के मामलों में कमी आई है, अतः हम कह सकते हैं, कि टीका लगने के पश्चात भी अगर पूरी सावधानी बरती जाए तो हमें

इस घातक वायरस से जल्दी छुटकारा मिल सकता है द्य किसी भी देश के सर्वांगीण विकास एवं समृद्धि हेतु नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होना चाहिए, किंतु यहां भी तथाकथित राजनीतिक दलों द्वारा राजनीति करने का अवसर नहीं खोने दिया जा रहा है। यहां तक की लाशों पर भी राजनीति की गई, जो कि बहुत ही निराशाजनक स्थिति है, इसके आगे तो मानवीय संवेदना में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता।

भारत देश में टीकाकरण की बात करें तो अभी टीका लगने की रफ्तार काफी कम है, क्योंकि टीके का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है, वर्तमान में पूरे देश में 67 हजार टीका केंद्र है, किंतु टीके की कमी के कारण केवल 44 हजार टीका केंद्र ही टीका लगा पा रहे हैं । यह सुखद बात है कि सरकार द्वारा टीकाकरण हेतु सात कंपनियों से समझौता कर लिया गया है तथा साल के अंत तक छह और कंपनियों से समझौता हो जाने के पश्चात टीकाकरण में पर्याप्त रफ्तार आ सकेगी, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

नागरिकों की सुरक्षा न केवल सरकार का कर्तव्य है, वरन यह नागरिकों का अधिकार भी है। इस हेतु सत्तारूढ दल द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है। नागरिकों के बीच स्वास्थ्य से संबंधित सभी आवश्यक बातों का प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, जिसके लिए मीडिया के साधनों जैसे टीवी, रेडियो, फोन, पत्र पत्रिकाएं ,अखबार की सहायता ली जा रही है। इन मीडिया के साधनों के द्वारा आम जनता में कोरोना से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं तथा आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।

इतना सब होने के बावजूद भी , इतने प्रयासों के बीच तथा इतनी बडो जनसंख्या (जहां भारत के कुछ राज्यों की जनसंख्या ही, कई देशों की जनसंख्या के योग के बराबर है), गलती होना सामान्य सी बात है। यहां हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे भी स्वयं के प्रति , समाज, परिवार, समुदाय के प्रति कुछ कर्त्तव्य हैं ,हम केवल राम भरोसे या सरकार के भरोसे ही अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, बल्कि हमें स्वयं आगे आकर इस कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी सेवाएं देनी होगी।

सरकार अपने दायित्व निभा रही है, और इन दायित्व को निभाने में अगर कुछ गलती हो भी रही है, तो यह विपक्ष तथा अन्य दलों का भी कर्तव्य है कि वह न केवल अपना बहुमूल्य समय सरकार को नीचा दिखाने में अथवा उनकी गलतियों को जनता के सामने लाने में करें, वरन स्वयं भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व केवल सत्तारूढ दल पर डाल देना कहां तक उचित है? हमारे संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही यह कहा गया है  कि भारत राज्यों का एक संघ है द्य इसी के साथ भारतवर्ष के कई राज्यों में विपक्ष या अन्य दलों की सरकार भी हो सकती है,  हमारे देश में राज्यों को भी स्वायत्तता प्राप्त है स अतः राज्यों को भी अपने राज्य के नागरिकों की सुरक्षा हेतु केवल केंद्र का मुंह देखने के बजाय स्वयं भी प्रयास करने चाहिए , किंतु देखने में यह आता है कि जब राज्यों के लिए, करों की वसूली तथा राजस्व संग्रहण की बात आती है तब तो राज्य केंद्र का दखल भी पसंद नहीं करते, वही जब खर्च करने की बात आए , तो केंद्र की तरफ से अनुदान मांगने लगते हैं, जोकि सरासर अनैतिक है। जिस तरह से कई राज्यों द्वारा टीके तथा वेंटिलेटर मशीनों को नालों में तथा अटाले में रखने की खबरें अखबार में प्रकाशित हो रही है , वह इस देश की एकता व अखंडता के प्रति बहुत ही असंगत व अन्यायपूर्ण बात है।

इस विकट परिस्थिति में तो केंद्र व राज्य सरकार को मिलकर सदभावना पूर्वक बिना किसी राजनीतिक अवसर को भुनाते हुए 'वसुधैव कुटुंबकम' की धारणा को चरितार्थ करना चाहिए। देश का नागरिक सर्वप्रथम भारत देश का नागरिक है, ना कि किसी राज्य का, या जिले या गांव का।

अभी सभी राजनीतिक दलों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि सभी राजनीतिक दल तथा राजनेता अपने भाषण में टीकाकरण को लेकर किसो भी प्रकार का विवादास्पद बयान देने से बचें। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, सभी राजनीतिक दलों को मिलजुल कर अपनी नीतियों का इस प्रकार प्रचार–प्रसार करना चाहिए, जिससे टीकाकरण को प्रोत्साहन मिल सके तथा आम जनता में टीकाकरण को लेकर जो भी भय् या गलतफहमियां व्याप्त है, उन्हें दूर किया जा सके, ना कि टीकाकरण को लेकर लोगों में और गलतफहमियों को बढावा दिया जाए।

टीकाकरण कार्यक्रम में टीके की बर्बादी को रोकने हेतु भी कड कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे तो सरकार द्वारा सभी को टीके मुफ्त में ही लगवाए जा रहे हैं, किंतु सक्षम व अमीर लोगों को आगे रहकर टीको को खरीद कर टीके लगवाना चाहिए।

टीकाकरण के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फिल्मी तथा क्रिकेट जगत की हस्तियों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि आम जनता इन लोगो की बहुत ही बडो प्रशंसक होती  हैं। अगर यह आम जनता से अपील करेंगे, तो जनता का उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पडगा तथा वे भी टीकाकरण करने के लिए प्रोत्साहित होगी। टीकाकरण को किसी भी संप्रदाय या जाति धर्म से नहीं जोडकर देखा जाना चाहिए। टीकाकरण से संबंधित किसी भी अफवाह को फिर भले ही वह

डिजिटल रूप से ही क्यों ना  फैलाई जा रही हो, उसके खिलाफ त्वरित कार्यवाही कर उसे बंद करवाना ही चाहिए।

अब केंद्र सरकार द्वारा, राज्यों को टीके मुफ्त में देने का जो निर्णय लिया गया है, वह भले ही कतिपय कारणों से देरी से लिया गया हो, पर यह सराहनीय कदम है, इससे जहां नागरिकों को समय पर टीके उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड भी नहीं होगा तथा उन्हें टीका लगवाने के लिए लंबे समय का इंतजार भी नहीं करना पडगा, वहीं दूसरी ओर सरकार के इस कदम से केंद्र का प्रभाव और मजबूत हुआ है, जिसका निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा।

अतः हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान में सबसे बडी चुनौती इस घातक कोविड वायरस को टीका करण तथा अन्य चिकित्सकीय उपायों के माध्यम से पूरी तरह से खत्म करने की हैं तथा जीवन को पुनः पटरी पर लाने की है और इस हेतु सरकार एवं विपक्षो दल सभी को मिलकर काम करना होगा द्य भगवत गीता में कहा भी गया है 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' अर्थात कर्म करते रहो फल की इच्छा मत करो। इस प्रकार कहा जा सकता है की देर–सवेर जनता का जो भी रुख राजनीतिक दलों के प्रति होगा, वह सभी को पता चल ही जाएगा।

टिप्पणी

राजनीतिक अवसरवादिता नैतिकता से अलग दोषयुक्त वातावरण में सिद्धांतो पर चलने की आशा करना काल्पनिक है।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची


- https://navbharattimes.indiatimes.com/india/corona-vaccine-registration-faq-in-hindi-covid-tika-ke-liye-kaise-register-karen/articleshow/81240700.cms
- https://www.financialexpress.com/hindi/india-news/govt-allow-covid19-vaccination-for-above-18-years-age-group-how-to-get-registration-here-is-full-process/2236447/
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1721950
- https://www.jagran.com/news/national-covid-vaccination-for-adults-know-the-complete-process-of-how-and-where-to-register-for-vaccination-21597903.html
- https://www.patrika.com/bikaner-news/covid-vaccination-6891612/
- http://gmch.gov.in/sites/default/files/documents/General%20Information%20about%20COVID%2019%20vaccine.pdf

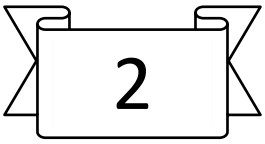

2

# कोविड टीकाकरण अभियानः निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका

राम किशोर

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पिछले कुछ महीनों की अवधि में, भारत में जैसे—जैसे लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके, पाबंदियां हटाई जा रही हैं, वैसे—वैसे लोगो की दिलचस्पी कोविड—19 के आंकडों से कम होती जा रही है। फिर चाहे बात नए संक्रमणों की हो, रिकवरी की या इस महामारी से मौत के आकड़ों की हो। वहीं दूसरी ओर, अब लोगों की दिलचस्पी एवं उत्सुकता कोविड—19 के टीकों में बढती जा रही है, जिनकी सहायता से इस जानलेवा महामारी से बचा जा सकता है। इस समय कोविड—19 को लेकर होने वाली परिचर्चा में तीन प्रश्न सबसे अधिक हावी हैं। कौन से टीके उपलब्ध हैं? ये टीके कब लगवाए जा सकते हैं? और, किसको ये टीके मिलेंगे अथवा लगेगें?

इस समय विश्व में कोरोना विषाणु से बचाने वाले टीकों की भारी मांग है। हर देश को अपने नागरिकों के लिए टीकों की आवश्यकता है। शुरुआती महीनों में इस प्रश्न से जुडी दो चिंताएं भी थीं क्या भारत के पास इतने वित्तीय संसाधन हैं कि वो अपनी बडी जनसंख्या को लगाने के लिए कोई टीके की पर्याप्त खुराक का प्रबंध कर सके? और शायद इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि, क्या भारत के पास अपने हर क्षेत्र में वैक्सीन के वितरण, भंडारण एवं लगाने के लिए पर्याप्त क्षमता तथा संसाधन हैं? क्योंकि, इतनी बडी जनसंख्या को टीका लगाने के लिए सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है।

देश भर में कोविड—19 के टीकाकरण में आने वाली चुनौतियों को लेकर उठ रहे प्रश्नो के उत्तर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में दे दिए थे। जब उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कहा था कि, 'सरकार हर भारतीय नागरिक को कोविड—19 का टीका लगाने के तरीकों पर विचार—विमर्श कर रही है। जैसे ही भारत में कोविड—19 की वैक्सीन आएगी, वैसे ही सरकार हर नागरिक को तेजी से ये टीका उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। तब से अब तक भारत ने टीकाकरण अभियान की दिशा में काफी प्रगति कर ली है। इस साल 16 जनवरी से देश

भर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रपक्ति कर्मियों (अर्थात सफाईकर्मियों, पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों) को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी जा रही है। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में 50 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को टीका लगेगा, जिन्हें अन्य बीमारियां भी हैं। भारत ने जुलाई–अगस्त 2021 तक 20–25 करोड लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है।

ये इस बात पर निर्भर करेगा कि टीकाकरण अभियान कितना तेज और व्यापक है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की महामारी की न तो कम हुई है और न ही ये वर्ष 2021 में समाप्त होने जा रही है। महाराष्ट्र और केरल में जिस तरह से नए संक्रमण बढने के बाद पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो इस बात का सबूत हैं। ऐसे में कोविड–19 पर भारत की जीत या हार का लोगों की जदिगी के साथ–साथ उनकी रोजी–रोटी से भी गहरा संबंध है। यही कारण है कि आज कोविड–19 का टीकाकरण अभियान सिर्फ लोगों के स्वाथ्य का विषय नहीं है ब्लकि यह एक राजनीतिक विषय बन चुका हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर मची होड के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते रहे हैं कि भारत टीकाकरण का अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। भारत का वैक्सीन मैत्री अभियान इसकी मिसाल बन चुका है। जब दुनिया के सभी अमीर देश अपने लिए अधिक से अधिक टीके प्राप्त करने में लगे हैं, तब भारत ने करीब बीस देशों को अपने वैक्सीन मैत्री अभियान के अंतर्गत कोविड–19 के टीकों की खुराक उपलब्ध करायी है।

यद्यपि, तथ्य अक्सर सरकारी दावों के उलट होते है, भारत में टीकाकरण अभियान तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी टीकों के मूल्य का प्रश्न अनुत्तरित है। क्योंकि पहले चरण में जिन्हें टीका लगाया जा रहा है, उसका खर्च सरकार उठा रही है, और टीका बना रही कंपनियों ने सरकार को ये टीका रियायती दरों पर उपलब्ध कराया है। किंतु अभी कोविड–19 का टीका देश में आसानी से सबके लिए सुलभ नहीं है। टीकों के दाम तय नहीं किए गए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सरकार कानून के वो प्रावधान लागू करेगी, जिनसे टीके बनाने वाली भारतीय कंपनियों को इनका फॉर्मूला विकसित करने वाली विदेशी कंपनियों को लाइसेंस फीस देने से रोका जा सके? क्या सरकार कोविड के टीकों का दाम तय करेगी? क्या देश के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में लगेगी? अगर सरकार का अपना टीकाकरण अभियान गिने–चुने लोगों के लिए होगा, तो बाकी लोगों को टीका लगवाने के लिए क्या करना होगा? उन्हें इसके लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेगें? इसके लिए वैक्सीन खरीदने, उनके वितरण और

टीके लगाने का काम कौन करेगा? चूंकि, अभी टीकाकरण अभियान की बडी जम्मेदारी राज्य सरकारों पर ही है, तो क्या वो सभी नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने की क्षमता रखते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही बदहाल है और इस महामारी ने तो उस पर दबाव और भी बढा दिया है।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के अनुसार टीकाकरण अभियान के लिए एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह बनाया गया है, जो टीकाकरण अभियान के हर पहलू पर नजर रख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि देश के 'ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों तक टीका पहुंचाने के लिए ये विशेषज्ञ समूह नए दृष्टिकोण से काम ले रहा है.' वैसे तो भारत में टीकाकरण अभियान चलते हुए एक महीने से ज्यादा समय बीत चुका है. लकिन अभी भी इससे जुडे कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। देश के हर कोने तक कोविड–19 का टीका पहुंचाने के लिए बडे पैमाने पर क्षमता ही नहीं, पैसों की भी जरूरत होगी। जिससे अभूतपूर्व रफ्तार से वैक्सीन का वितरण देश भर में किया जा सके।

भारत को पोलियो टीकाकरण अभियान का अच्छा तजुर्बा रहा है. इस अभियान की तारीफ पूरी दुनिया में होती है. इस अभियान की कामयाबी के पीछे सबसे बडा हाथ डॉक्टर हर्षवर्धन का ही था. ऐसे में उन्हें अच्छे से पता होगा कि जुलाई 2021 तक 20–25 करोड भारतीयों को कोविड–19 वैक्सीन की 40–50 करोड खुराक कैसे उपलब्ध करायी जा सकती है।

हालांकि, भारत को पोलियो टीकाकरण अभियान का अच्छा तजुर्बा रहा है. इस अभियान की तारीफ पूरी दुनिया में होती है।

डॉक्टर हर्षवर्धन के आत्मविश्वास के पीछे, टीकाकरण अभियान में भारत का लंबा तजुर्बा है। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बडा टीकाकरण अभियान चलाता रहा है। हर साल देश में 2.7 करोड नवजात बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। भारत के पास टीकों की आपूर्ति, उनके भंडारण और दूर–दराज के इलाकों तक टीके पहुंचाने का बुनियादी ढांचा पहले से स्थापित है. इसके लिए सरकार ने पहले से बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म **e&Vin (electronic Vaccine Intelligent Network)** को अपग्रेड करके उसे **Co&Win (Covid&Vaccine Intelligent Work)** का नाम दिया गया है. इसे आरोग्य सेतु ऐप से भी जोडा गया है, जिससे जरूरतमंद लोगों की पहचान करके उन तक वैक्सीन को आसानी से पहुंचाया जा सके। इसके अलावा भारत अपने विशेष पहचान पत्र **(UID)** अर्थात आधार के डेटाबेस का भी इस्तेमाल कर रहा है। जिससे

राष्ट्रीय सुरक्षा की इस जरूरत अर्थात टीकाकरण अभियान में सहायता मिल सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि 135 करोड से अधिक जनसंख्या वाले देश में कोरोना वायरस के टीकों की अधिक मांग है और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव भी अधिक है।

पहले चरण के टीकाकरण को मुफ्त करने और दूसरे चरण में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तो रखा गया है। पर सरकार इसके बाद बाकी नागरिकों को कैसे टीका उपलब्ध कराएगी? उसकी कीमत क्या होगी? टीके लगाने का खर्च कौन वहन करेगा? इन सभी सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन देने में भारी रकम खर्च होगी। सीरम इस्टीट्यूट के अदार पूनावाला का आकलन है कि इसमें 80 हजार करोड रुपए का खर्च आएगा। लेकिन, ये तो सिर्फ वैक्सीन की लागत है। वैक्सीन के वितरण, उसके भंडारण और टीके लगाने का खर्च इससे अलग होगा। यद्यपि, इस आकलन के सामने आने के बाद भारत के व्यय सचिव टी वी सोमनाथन ने ऐसी चिंताओं को खारिज किया था कि सबको टीके लगाने की राह में पैसे की समस्या आ सकती है। उन्होंने कहा था कि टीके लगाने की राह में पैसे की कमी की समस्या नहीं आने दी जाएगी, एवं अभावग्रस्त लोगों को टीका लगाना हमारा कर्तव्य है।

अगर देश के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस का टीका देने का निर्णय किया जाता है, तो इसके लिए कुछ पैमाने तय करने होंगे। अतः मोटे तौर पर भारत ने जुलाई 2021 तक 20–25 करोड लोगों को कोविड वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार पैसे की कमी नहीं होने देने का वादा कर रही है। अब तक का कोविड–19 टीकाकरण अभियान निशुल्क ही चलाया जा रहा है। आगे क्या होगा, ये सरकार ही बता सकती हैं। अगर देश के सभी नागरिकों को कोरोना वायरस का टीका देने का निर्णय किया जाता है, तो इसके लिए कुछ नियम निश्चित करने होंगे। केंद्र सरकार को इस बात का विश्वास है कि वो पूरे देश में टीकाकरण अभियान चला सकती है। लेकिन, अब तक की योजना के अनुसार देखें तो कोरोना वैक्सीन लगाने के अभियान में भारत की कुल 135 करोड जनसंख्या में से एक चौथाई से भी कम लोगों को इसक दायरे में रखा गया है। यद्यपि, विकसित देशों की तुलना में 20–25 करोड लोगों को भी टीका लगाने का आंकडा भी बहुत बडा है। लेकिन, हमारे देश की जनसंख्या भी तो अधिक है। फिर भी, देश के एक चौथाई लोगों को कोविड–19 का टीका लगाने की आदर्श स्थिति से अब भी हम बहुत दूर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस टीकाकरण कार्यक्रम का दायरा बढाने के लिए सरकार निजी क्षेत्र को भागीदार बनाने से क्यों हिचक रही है?

इस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। लोगों की रोजी–रोटी पर गहरा असर पडा है। भारत, लोगों की जान बचा पाने में काफी हद तक सफल रहा है। लेकिन, कोरोना वायरस के टीकाकरण अभियान में भागीदारी भारत के बड कारोबारियों के लिए भी फायदे का ही सौदा होगी। उन्हें अपनी शक्ति इस अभियान में लगानी चाहिए। इससे करोडों भारतीयों को टीका लगाने की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। सरकार का बोझ हल्का होगा, तो वो गरीबों और समाज के ऐसे निर्बल लोगों की सहायता पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगी, जिनकी जान को इस महामारी और दूसरी बीमारियों से सबसे अधिक खतरा है।

देश की बडी कंपनियों को अपने–अपने स्तर पर कोरोना वायरस का टीका लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्हें कम से कम अपने कर्मचारियों, उनके परिजनों और अन्य सहयोगियों को अपने खर्च पर टीके लगाने का विकल्प दिया जा सकता है। केंद्र की एजेंसियां और स्वास्थ्य मंत्रालय इस काम की निगरानो कर सकते हैं। उन्हें खुले बाजार से वैक्सीन निर्माताओं से टीके खरीदने के सौदे करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

निजी कंपनियां, टीकाकरण अभियान के लिए निजी अस्पतालों के कर्मचारियों की मदद ले सकती हैं। जिन कंपनियों के पास अपनी जरूरत से अधिक टीके खरीदने की क्षमता है, वो बचे हुए टीकों से सरकार की मदद भी कर सकती हैं। या फिर वो इन टीकों से अपने कर्मचारियों के अलावा, अपनी आपूर्ति श्रृंखला से जुड लोगों और परिवारों को टीके लगाने का काम कर सकती हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी से करोडों भारतीयों को बडो तेजी के साथ टीके लगाए जा सकते हैं। इससे देश के उद्योग जगत की कोविड–19 महामारी से लडने की ताकत ही बढगी। इससे वो अपने कारोबार पर पड़ने वाले महामारी के दुष्प्रभावों से बच सकेंगे। अपना उत्पादन बढा सकेंगे। टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र की भागीदारी से लोगों की जिंदगी के साथ–साथ उनकी रोजी–रोजगार को भी बचाया जा सकेगा।

किसी महामारी या संक्रामक रोग से निपटने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं होनी चाहिए। महामारी से लडने के सरकार के प्रयासों को 'कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी' या निजी क्षेत्र द्वारा उठाई जा सकने वाली सामाजिक जिम्मेदारियों से भी मदद मिलनी चाहिए। ये काम केवल कंपनी द्वारा अपने वार्षिक लाभ के वितरण तक सीमित नहीं होना चाहिए।

इस महामारी के शुरुआती दौर में हमने देखा था कि सरकार को बुनियादी जरूरतों जैसे कि टेस्ट किट की आपूर्ति में ही बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी भारी

कमी थी। जब इस काम में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाया गया, तभी जाकर भारत में कोविड–19 के टेस्ट ने रफतार पकडो थी। यही वजह थी कि जैसे–जैसे कोरोना की महामारी बढो, उससे निपटने में देश और सक्षम होता नजर आया था।? इसी प्रकार, जब इस महामारी ने हमला बोला, तो देश में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी निजी सुरक्षा के उपकरणों (PPE), मास्क और शरीर ढकने वाले कवर की भारी और मुश्किल बढाने वाली कमी हो गई थी. यहां तक कि जब इन्हें खरीदा भी जा सकता था, तो अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होने से ये सामान भारत पहुंचने में देर हो रही थी। भारत को सख्त जरूरत होने के बावजूद अक्सर ये सामान कहीं और भेज दिए जाने की मिसालें भी हमने देखी थीं।

तभी निजी सुरक्षा उपकरण (PPE) बनाने में निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाया गया। इसके बाद तो तस्वीर बिल्कुल ही बदल गई, एवं पहले जहां भारत इन सामानों का खरीदार भर था वहीं, आज भारत निजी सुरक्षा उपकरणों का एक बडा निर्यातक देश बन चुका है। ये बदलाव निजी क्षेत्र की सुदृढ़ भागीदारी और राष्ट्रीय स्तर के प्रयासों से ही आया है। इस महामारी के शुरुआती दौर में हमने देखा था कि सरकार को बुनियादी जरूरतों जैसे कि टेस्ट किट की आपूर्ति में ही बहुत मशक्कत करनी पडो थी। स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी भारी कमी थी। जब इस काम में निजी क्षेत्र को भागीदार बनाया गया, तभी जाकर भारत में काविड–19 के टेस्ट ने रफतार पकडो थी।

इसी तरह अगर निजी क्षेत्र को टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाता है। उन्हें अपने स्तर पर टीके लगाने की छूट दी जाती है। तो, ये कदम भी टीकाकरण अभियान की दशा–दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। लेकिन, ऐसा होने के लिए राष्ट्रीय कोविड निरोधक अभियान के मंच पर सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र को तुरंत जोडने की आवश्यकता है।

कोविड टीकाकरण अभियान के लिए बने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह को केवल सरकारी कर्मचारियों एवं महामारी विशेषज्ञों का विशिष्ट क्लब नहीं बनाया जाना चाहिए ब्लकि इसके सदस्यों का दायरा बढाकर इसमें निजी क्षेत्र को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए। टीकाकरण अभियान में सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी के बारे में उनकी राय भी ली जानी चाहिए। इसके पश्चात् एक ऐसा प्रतिमान तैयार किया जाना चाहिए, जिससे टीकाकरण अभियान को कुशलतापूर्वक, तीव्र गति एवं व्यापक ढंग से चलाया जा सके। सरकार का प्राथमिक उत्तरदायित्व लोगों के जीवन की सुरक्षा है। लोगों की रोजी–रोटी बचाने में निजी क्षेत्र को भी जम्मिेदारी निभाने का अवसर दिया जाना चाहिए।

बहुत सी बडी कंपनियां हैं जो अपने संसाधन लगाकर कोविड–19 के टीकाकरण अभियान में सहायता के लिए तैयार हैं। वो स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन को काफी मात्रा में खरीदकर, ऐसे टीकों का भंडारण, उनकी आपूर्ति करने और अपने स्तर पर टीका लगाने की जम्मिेदारी निभाने के लिए भी तैयार हैं। उनके पास इस बात की क्षमता है कि वो टीके लगाने की रफतार और दायरा दोनों को बढा सकें। निजी क्षेत्र के माध्यम से ऐसे लोगों को भी कोरोना वायरस का टीका दिया जा सकता है, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उनके अपने कर्मचारी नहीं हैं। अगर कोरोना के टीकाकरण अभियान में हम देश के निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं को भी सम्मिलित कर लें, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी (PPP) का ये प्रतिमान कोविड टीकाकरण अभियान को कई गुना बडा बना सकता है।

अब ये सरकार को निश्चित करना है कि वो पहले चरण में 20–25 करोड लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाकर संतुष्ट हो जाना चाहती है। अथवा, वैक्सीन की खुराक देने के इस लक्ष्य को निजी क्षेत्र की सहायता से और बडा बनाना चाहती है। ये एक ऐसा निर्णय है जिसे हम किसी और समय के लिए नहीं टाल सकते हैं।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची


- https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/translation/hi/register
- https://www.mygov.in/hi/covid-19
- https://www.unicef.org/india/hi/node/1636
- https://www.unicef.org/india/hi/story/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A1-19-%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%B6%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%86%E0%A4%A4
- https://www.orfonline.org/hindi/research/india-needs-private-and-public-sector-for-vaccination-of-covid-19/

3

# भारत में कोविड टीकाकरण की बदलती नीति एवं बढ़ती राजनीति

डॉ. अमित अग्रवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य), राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुर, उत्तर प्रदेश

भारत 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। भारत में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल, 53 क्षेत्रीय राजनीतिक दल और 2044 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। भारत में लोगों के खून में राजनीति समा गई है। वैश्विक रहस्यमयी महामारी कोरोना वर्ष 2020 के आरंभ में भारत में प्रवेश कर गई। कोविड–19 के कारण वैश्विक स्तर पर मानव के जीवन के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। कोरोना से लड़ी जा रही जंग में प्रत्येक देश का यही प्रयास है कि कोरोना से जल्द से जल्द निजात पाई जा सके और इसके लिए दुनियाभर में कोविड टीकाकरण (वैक्सीनेशन) का कार्य चल भी रहा है। इस महामारी को रोकने के लिए देश में वर्ष 2021 के आरंभ में टीकाकरण की रणनीति बनाना आरंभ हुई। विपक्षी दलों को कोरोना महामारी एक राजनीतिक अवसर के रूप में दिखी जिसके कारण भारत में कोविड–19 टीकाकरण पर राजनीति इसके अनुसंधान के साथ ही शुरू हो गई और आज तक अनवरत जारी है।

## क्यों जरूरी है कोविड–19 टीकाकरण

टीकाकरण पर राजनीति जरूरी है या नागरिकों को टीका लगाना जरूरी है ज्वलंत प्रश्न है। भारत में अभी दूसरी लहर चल रही है और तीसरी लहर को रोकने के लिए या तीसरी लहर अत्यधिक सीमित करने के लिए सभी वयस्कों को टीका लगाना नितांत जरूरी है। यदि मनुष्य जीवित रहेगा तो राजनीति बाद में भी हो जाएगी। लाशों पर राजनीति करके क्या फायदा। सभी को टीकाकरण करने की रणनीति प्राथमिकता से बनानी चाहिए जिसमें केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार का सहयोग और समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। संक्रमण को रोकने के लिए देश में टीकाकरण का अभियान जारी है। जून मध्य तक 25 करोड़ से ज्यादा टीके भारत में लगाए जा चुके थे। टीके से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। यह प्रतिरोधक क्षमता 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक शरीर में रहती है। यह प्रतिरोधक क्षमता शरीर में गंभीर संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है।

कोविड–19 टीकाकरण पर राजनीति के मुख्य मुद्दे

भारत देश की वर्तमान आबादी 135 करोड़ के लगभग है जो देश के 600000 से अधिक गांवों और 5000 से अधिक कस्बों, शहरों और महानगरों में निवास करती है। इस विशाल जनसंख्या तक टीकाकरण करना कोई सरल कार्य नहीं है। छिद्रान्वेषण करना मनुष्य का स्वभाव या मनोवृत्ति है। अतः राजनीतिक दल इस से दूर कहाँ रह सकते हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा, "यह काफी अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे राजनेता भी हैं जिन्होंने टीकाकरण के मुद्दे पर अनावश्यक राजनीति में लिप्त होने का रास्ता चुना है और हर कदम पर गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। हमारे कोविड–19 टीके की प्रभावशीलता, उसकी कीमत जैसे तमाम मुद्दों पर गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। उपचार और वैक्सीन की कमी को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो निराधार हैं क्योंकि देश में इनकी कोई कमी नहीं है।" *टीकाकरण को लेकर राजनीति के निम्नलिखित कारक या मुद्दे हो सकते हैं–*

1. माँग–आपूर्ति में अंतराल– भारत देश में भी टीकाकरण की शुरुआत की, आपूर्ति और माँग में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं थी। टीकाकरण केंद्रों पर आवश्यकता के अनुरूप टीके उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिसके कारण राज्य सरकारों को टीकाकरण अभियान को बीच–बीच में रोकना पड़ रहा है। माँग के अनुरूप टीकों की आपूर्ति नहीं हो पा रही है अर्थात माँग के अनुरूप टीकों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। विपक्षी दलों के शासन वाले लगभग सभी राज्यों ने एक साथ केंद्र को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए पहले ही तरह केंद्रीकृत तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की अपील की है। भारत की जनसंख्या अत्यधिक विशाल है। वैश्विक स्तर पर माँग के अनुरूप टीकों की आपूर्ति करने में विकसित और विकासशील देश असफल रहे हैं, जो विपक्षी दलों को राजनीति करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। जनता की नाराजगो का लाभ उठाने के लिए राजनीतिक दल लालायित हैं। अब 31 दिसंबर तक 187.2 करोड़ वैक्सीन की उपलब्धता सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। 1 अगस्त से 31 दिसंबर के बीद तकरीबन 133.6 करोड़ डोज लोगों को लगाई जाएगी और हर रोज 90 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।

2. टीके की कीमत नीति– टीके का उत्पादन करने वाली विभिन्न कंपनियाँ राज्य सरकारों एवं निजी कंपनियों को अलग–अलग मूल्यों पर टीका उपलब्ध करा रही हैं जिसके कारण राजनीतिक दल इसकी आलोचना कर रहे हैं और यह मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। केंद्र अब तक केवल 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका उपलब्ध करा रहा था।

यह टीके केंद्र ने निर्माताओं से 157 रुपये प्रति डोज की दर से खरीदे थे। जबकि, राज्यों ने सीरम इंस्टीट्यूट को 18–44 वर्ग के लिए 300–400 रुपये प्रति डोज दिए हैं।

3. स्वदेशी बनाम विदेशी टीका– भारत के औषध महानियंत्रक ने दो 'मेड इन इंडिया' टीकों भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड को कोविड–19 प्रबंधन नीति के तहत आपात उपयोग की मंजूरी (ईयूए) दी है। रूस निर्मित स्पुतनिक वी को भी भारत में इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है। अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी के अनुसार, 'इस समय कोविड–19 के 88 टीकों का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है, जबकि 184 टीके विकास के पूर्व–नैदानिक चरण में हैं।' विवाद का मुद्दा यह है कि स्वदेशी टीके का उपयोग किया जाए अथवा विदेशी का। क्या स्वदेशी टीके भारत की माँग को पूरा करने में सक्षम हैं।

4. टीके का निर्यात– वसुधैव कुटुम्बकम् यह वाक्य इसका अर्थ है, ये पृथ्वी ही अपना परिवार है। टीका कूटनीति शुरू करने के दो महीने से भी कम समय में, मोदी सरकार 91 देशों को वैक्सिन की लगभग 66 मिलियन खुराकें बांट चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने इस आउटरीच को 'वैक्सीन मैत्री' करार दिया है। यह बेहद सराहनीय कार्य है। इस त्रासदी में वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प दिखा, टीका की मांग बढ़ने लगी जिसके कारण कई राजनीतिक दल टीका के अन्य देशों में देने पर सवाल भी उठा रहे हैं।

5. कोविन ऐप– ग्रामीण भारत एवं शहरी इण्डिया के बीच विशाल डिजिटल अंतराल के बाद भी टीके के स्लॉट बुक कराने के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य को लेकर केंद्र के फैसले की आलोचना की गई थी। कोविन ऐप प्रधानमंत्री की फोटो पर गैर भाजपा वाले राज्यों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

6. मुफ्त बनाम सशुल्क टीका– भारत सरकार ने 45 वर्ष एवं उससे ऊपर के व्यक्तियों को निशुल्क टीका लगाया इससे कम आयु वर्ग के लोगों के लिए भी मुफ्त टीका लगाने की माँग राजनीतिक दल करते रहें। भारत सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए भी टीका मुफ्त देने की घोषणा की है।

7. केंद्र बनाम राज्य द्वारा टीके की क्रय नीति– 08 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनः कोरोना के टीकाकरण अभियान के कमान केंद्र सरकार को सौंप दी है। मोदी ने कई विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयानों का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए यह भी कहा कि

टीकाकरण को लेकर राजनीतिक छींटाकसी उचित नहीं है। 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की टीकाकरण की नीति में बदलाव करते हुए राज्य सरकार को अधिकार दिया कि वो भी टीका की खरीद कर सकते हैं। अहम बात यह है कि कई राज्यों ने टीका की खरीद में असमर्थता जाहिर करते हुए राज्य से इसकी खरीद की अपील की थी।

8. टीके पर कर नीति– भारत सरकार ने कोविड टीके पर जीएसटी लगा रखा है। आयातित टीके आयात शुल्क और जीएसटी के कारण स्वदेश में उत्पादित टीकों की तुलना में बहुत महंगे होंगे। विपक्षी दलों द्वारा जीएसटी लगाने को आम जनता पर भार माना गया है जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि हम मुफ्त टीका दे रहे हैं अतः इसका भार जनता पर नहीं पड़ेगा।

9. जनता को टीका लगवाने के मध्य अंतराल– वैक्सीन की डोज के बीच गैप को बढ़ाए जाने के बाद इसको लेकर बहस और भी तेज हो गई है। एक वैक्सीन के बीच गैप न बढ़ाकर पहले जैसा ही वहीं दूसरी वैक्सीन के बीच गैप आखिर क्यों बढ़ाया गया। अमेरिकी डॉक्टर फाउची ने चेताया है कि कोरोना वैक्सीन क बीच का अंतराल बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। केंद्र को इन आयातित टीकों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि दूसरी खुराक के वक्त इनकी कमी न हो।

10. टीके का वितरण, भण्डारण एवं रखरखाव नीति– केंद्र सरकार कुल वैक्सीन उत्पोदन का 75 फीसदी खरीदेगी और फिर राज्यों को उन प्राथमिकता के आधार पर वितरण करेगी। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही चरमराई हुई है। अगर भारत अपने टीकाकरण अभियान को तेज गति से चलाना चाहता है, तो टीकों की पर्याप्त खुराक जुटा पाना एक समस्या हो सकती है। प्राथमिकता समूहों के अलावा 45 से अधिक आयु वर्ग के लोग और 18–44 आयु वर्ग के लोगों को फ्री में टीका लगाएगी। राज्यों को ऐक्टिव केसलोड, वैक्सीानेशन की परफॉर्मेंस और बर्बादी के आधार पर डोज अलॉट की जाएंगी।

11. विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टीके को मान्यता– विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित कोविशील्ड को अपने समर्थन की हरी झंडी दिखाई है किंतु कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है, जिससे राजनीतिक दलों को खिंचाई करने का एक नया मुद्दा मिल गया। विदेश में जाने वाले भारतीयों को पुनः टीका लगवाना पड़ रहा है।

12. जनता को टीका लगाने की रफ्तार– राजनीतिक कारणों से भारत निर्मित वैक्सीन के प्रति लोगों में अविश्वास फैल गया, इसके फलस्वरूप यहाँ टीकाकरण की गति धीमी हो गयी। लोगों

में अविश्वास के कारण, कई राज्यों में लाखों टीके बर्बाद भी हुए। अगर देश भर में फैले 29 हजार टीकाकरण केंद्रों में प्रतिदिन लगभग 200 लोगों को वैक्सीन दी सके, तो भारत का कोविड–19 टीकाकरण अभियान केवल दो महीनों में ही खत्म हो सकता है।

13. अदान पूनावाला का लंदन जाना– कोरोना रोधी वैक्सीन कोविशील्ड की निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने खुद बताया है कि उन्हें वैक्सीन के लिए देश के ताकतवर लोग धमका रहे हैं। इसलिए वे अभी ब्रिटेन से भारत नहीं लौटेंगे।

14. जनता में टीके को लेकर हिचकिचाहट व जागरूकता – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अनेक जागरूकता कार्यक्रमों में से एक 11–14 अप्रैल तक 'टीका उत्सव' क आयोजन किया गया। सरकार का मानना है कि टीकाकरण के बारे में अधिक जागरूकता भारत को कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में अधिक सक्षम बनाएगी। लोगों में टीका लगवाने के प्रति हिचक देखने को मिली है. इस हिचक के पीछे लोगों के बीच महामारी एवं टीके के बारे में गलत सूचना के प्रसार को वजह माना जा रहा हैं।

15. न्यायालय समीक्षा– गौरतलब है कि बीते दिनों टीकाकरण नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की फटकार लगाई थी और इसे 'मनमाना' करार देते हुए समीक्षा करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने यह भी जानना चाहा था कि टीकाकरण के लिए निर्धारित 35,000 करोड़ रुपये अब तक कैसे खर्च किए गए और इसका उपयोग 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण पर क्यों नहीं किया जा सकता। अदालत के 31 मई के आदेश में उदारीकृत टीकाकरण नीति, केंद्र एवं राज्यों तथा निजी अस्पतालों के लिए टीके के अलग–अलग दाम आदि को लेकर केंद्र के फैसले की आलोचना की गई थी।

16. विभिन्न आयु वर्गो को टीकाकरण या सभी को एक साथ– कोविड–19 टीकाकरण की वर्तमान व्यवस्था के तहत पहले स्वास्थ्यकर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग, 45 से अधिक आयु के लाग और फिर 18 से 45 वर्ष से मध्य आयु के लोगों को टीके लगाए जा रहे है। केजरीवाल ने सभी आयु वर्ग के लिए टीकाकरण करने की मांग रखी थी कुछ राज्यों में डोर टू डोर टीकाकरण की भी मांग रखी है।

17. राज्यों के मध्य टीके की खुराक के आवंटन में भेदभाव– गर–बीजेपी शासित राज्यों का कहना है कि उनके पास इसके लिए पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। मोदी सरकार ने महामारी से निपटने में कोताही के लिए कुछ राज्य सरकारों की खिंचाई की और कुछ लोग इसे महज संयोग

नहीं मानते कि केंद्र ने जिन तीन राज्यों का उल्लेख किया है वहां गर–भाजपा सरकारें हैं। एक तरफ तो ये मामला है, वहीं ये हैरानी की बात नहीं है कि महामारी का ठीक से प्रबंधन नहीं कर पाने वाली राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही हैं।

निष्कर्षः संशोधित टीकाकरण नीति के अनुसार, 21 जून से 18 साल से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को सरकार फ्री में टीका लगाएगी। डॉ. हर्ष वर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के एक कार्यक्रम में जानबूझकर राजनीति और गलत सूचनाएं फैलाने की निंदा की। आज, समय की सबसे बड़ी माँग है कि हम एक–दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। भारत के संसद के मुख्य द्वार पर लिखी दो पंक्तियाँ भारत तथा हर भारतीय की आत्मा का प्रतीक है–

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।
उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम् ।।

♦♦♦♦♦

- **संदर्भ–सूची**


- https://www.mygov.in/covid-19
- https://nidm.gov.in/covid19/
- fofHkUu lekpkj i=

4

# कोविड़ टीकाकरणः शीघ्रता, सुगमता एवं बुद्धिमत्ता

सष्टि

शाधाथी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

टीकाकरण संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए एक आधारशिला है। कोरोना की तृतीय लहर से देश को संरक्षित व सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय टीकाकरण की शीघ्रता है। यह जितनी सुगमता से चलेगा उतनी ही शीघ्रता से हम वायरस से सुरक्षित होंगे। अधिक शीघ्रता के साथ प्रारंभ हुआ देश का यह कोविड़ टीकाकरण कार्यक्रम अभी धीमी गाती से प्रगति कर रहा है। अर्थात यह तभी सार्थक होगा जब जनता टीकाकरण के अभियान में भाग लेगी तथा सहभागी बनेगी, बिना किसी घबराहट व हिचक के लोग टीका लगवाने जाएंगे।

इसका कारण भ्रांतियाँ, टीकों की कमी व देश की विशाल जनसंख्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार, अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, ऐसे में बचाव का एकमात्र विकल्प टीकाकरण ही है। किन्तु देश के विभिन्न क्षेत्र व विशेषकर गावों में अभी जागरूकता की कमी है। इसके साथ ही अशिक्षा तथा निर्धनता भी टीकाकरण को लेकर एक भ्रम है। कोरोना टीकाकरण को लेकर विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचार फैलाएं गए है। धर्म के नाम पर भी कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में भय उत्पन्न किया जा रहा है।

लोगों के मन में विभिन्न प्रकार के डर बने हुए हैः– जैसे कि टीकाकरण से मृत्यु हो जाएगी या टीकाकरण से कोरोना वायरस जाएगा या नहीं, कोरोना टीकाकरण के स्थान पर कोई ओर दवा तो नहीं लगा दी जाएगी। या टीकाकरण के दुष्प्रभाव से भिन्न–भिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है। यद्यपि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सभी दावों को गलत ठहराया है। और इसके साथ–साथ यह भी बताया है कि टीकाकरण जान बचाता है, जान नहीं लेता। टीका लगवाने से कोरोना संक्रमण नहीं होता, टीका शरीर में न्यूटलाइजिंग एंटीबॉडीज बनती है। टीका लगवाने के पश्चात भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है, अपितु यह संक्रमण जब शरीर मे प्रवेश करेगा तब उसका मुकाबला करने के लिए हमारा शरीर पहले से तैयार रहेगा। वैक्सीन कोरोना होने पर भी गंभीर रूप से बीमार होने से बचाती है।

वास्तविकता तो यह हैं कि टीकाकरण से ही बड़ी संख्या मे लोग संक्रमित होने के पश्चात भी सुरक्षित रहे है। और कोरोना वायरस का उन पर प्रभाव तो हुआ अपितु अपनी जान बचाने मे वो सक्षम रहे।

लोगों के मन मे व्याप्त भ्रम व भय को समाप्त करके टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, तभी देश कोरोना मुफ्त हो सकेगा। टीकाकरण के प्रति विश्वास बढ़ाया जा सकता है। टीका लेने के उपरांत स्वास्थ्यकर्मी लोगों के मध्य जागरूकता उत्पन्न कर सकते है। इसके अतिरिक्त, नेताओं, अभिनेताओं तथा समाज व देश के प्रमुख व विशेष लोगों का टीकाकरण लाइव करके व उसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करके कोरोना टीकाकरण पर विश्वास बढ़ाया जा सकता है।

कोरोना टीकाकरण को लेकर फैले हुए भ्रम को दूर करने के लिए शिक्षण संस्थानों की सहायता भी ली जा सकती है। कोविड़ टीकाकरण के लाभ क्या है, यह किस प्रकार महामारी को रोकने मे लाभकारी हो सकता है तथा सरकार ने टीकाकरण के क्रियान्वयन के लिए किन–किन योजनाओं व प्रयोजनाओ का निर्माण किया है। इस सबके बारे में स्व; सेवक लोगों को बताएं और टीकाकरण के लिए जागरूक करे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालयों व विश्व–विद्यालयों की सहायता ली जा सकती है। और इसके लिए उन्हे प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, छात्र अपने घरों के आस–पास, पड़ोसियों, संबंधियों तक भी टीकाकरण से जुड़ी सही जानकारी पहुंचा सकते है। सरकार को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफोर्म के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक करने का अभियान चलाना चाहिए। निजी समाचार चौनलों को भी कोरोना वायरस के इलाज, संक्रमण से बचाव और टीकाकरण के बारे मे अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी चाहिए। कोरोना टीकाकरण को लेकर अधिकतर भय व आशंका ग्रामीण क्षेत्रों मे ही ह। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों मे वास्तविक व यथार्थ जानकारी तथा समुचित शिक्षा का अभाव है। अतः ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, सरपंच आदि को गाँव–गाँव व घर–घर जाकर लोगों की भ्रांतियाँ को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

इस अभियान के प्रचार–प्रसार के लिए प्रसिद्ध व प्रतिष्ठित व्यक्तियों की भी सहायता ली जा सकती है। महिलाएं धारावाहिक अधिक देखती है। टीकाकरण के लाभ से संबंधित एक कार्यक्रम बनाकर उन्हें जागरूक किया जा सकता है। क्योंकि यदि महिलाएं जागरूक होंगी तो वो अपने

पूरे परिवार को इसके प्रति समझा सकती है। और उन्हें भी जागरूक कर सकती है। इसके अतिरिक्त संप्रदाय विशेष मे टीकाकरण को लेकर अधिक भ्रांतियाँ बनी हुई है। इसके लिए सभी धर्मगुरुओं की सहायता ली जा सकती है। समाज के सभी धर्मगुरुओं को इस जागरूकता अभियान में अपना योगदान देना चाहिए। टीकाकरण को लेकर भ्रम फैलाने वाल देश के विरोधी है। शासन–प्रशासन के साथ–साथ हम सबका दायित्व है कि लोगों को जागरूक करें और टीका लगवाने मे सहयोग करे। अतः इस महामारी की स्थिति में एकमात्र टीकाकरण ही सुदृढ़ हथियार है। यही वास्तविक राष्ट्रभक्ति है।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची


- Dogra] Bharat- (2020). 'Crucial Questions for Covid Vaccine', Mainstream, Vol& LVIII No 41, New Delhi.
- Ninan] K N- (2021). 'Covid-19 Vaccines Politics, Nationalism and Diplomacy' Mainstream, Vol LlX No-10, New Delhi.
- प्रिय, दर्शनी, भ्रांति न पाले, समझदारी दिखाएं, 12 मई 2021, प्रष्ठ– संख्या– 10, राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली।
- एक और स्वदेशी टीका, 20 मई 2021, प्रष्ठ– संख्या– 10, राष्ट्रीय सहारा, नई दिल्ली।
- https.//www-who-int/emerencies/diseases/novel&coronavirus.2019/covid.vacciness

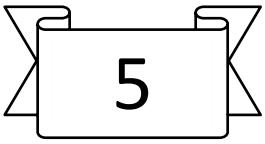

# कोरोना, टीकाकरण, मानवता एवं राजनीति

रजनी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

कोविड के चलते भारत के कई राज्यों को कालाबाजारी जैसी राजनीति से गुजरना पड़ा, जिसमें दवाईयों, ऑक्सीजन, एवं उपकरणों पर उच्च स्तर पर राजनीति का व्यापार देखने को मिला जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव रेमडेसिविर पर देखा गया। अनगिनत होने वाली मृत्यु जिसमें भले ही रेमडीसिविर की यर्थाथ में आवश्यकता थी या नहीं पर रेमडेसिविर के लिए होने वाली आपूर्ति दर्शाती है कि मात्र रेमडेसिविर को ही जैसे ऑक्सीजन की तुलना में उच्च स्तर पर देखा गया। वहीं उसकी बढ़ते हुए मूल्य यह दर्शाते रहे थे कि कोई नियम, निर्देश अब किसी के लिए शायद ही कोई मूल्य रख रहे थे, और साथ ही ऑक्सीजन की होने वाली कमी के कारण होने वाली राजनीति जिसमें दोषारोपण का प्रचार और प्रसार बखूबी देखा गया।

यही प्रकिया टीकाकरण में पुनः देखी गयी अर्थात केंद्र का राज्यों पर और राज्यों का केंद्र पर दोषारोपण करना। परंतु इसके अतिरिक्त कहा गया कि केंद्रिय मंत्रिमंडल के द्वारा टीकों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। घोषणा भी की गई कि वैक्सीन के रोलआउट क लिए तीसरे चरण को नियंत्रण में करने के लिए नियमों का निर्माण किया जाए। जिसके माध्यम से निजी बाजारों में टीकों को उतारा गया और केंद्र के द्वारा राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष रूप से टीके खरीदने की अनुमति प्रदान की गई, साथ ही 18 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को केंद्र सरकार मास मीडिया के द्वारा सामान्य जन को टीकों के बारे में जागरूक करने का कार्य भी सम्पन्न करने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही अन्य माध्यमों से टीकों तक पहुँच की अनुमति भी प्रदान की गई। जिस कारण उनके पास उत्पादित आधे टीकों का अधिकार होगा, और वह उसी रियायती दर का भुगतान भी करेगा जिस पर पहले सरकार और दो वैक्सीन उत्पादकों, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मध्य सहमति हुई थी। जिसे 45 वर्ष से अ की आयु के सामान्य जन के लिए खोलने का आदेश भी दिया गया। दामों में केंद्र सरकार के स्तर पर टीके 150 रूपये प्रति पर उपलब्ध होंगे, तो वहीं राज्य सरकारें एसआईआई के द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के विषय में एक सामान्य उच्च दाम 400 रूपये और निजी

बाजार के माध्यम से दर की दाम 600 रूपये से अधिक रखा गया। कोवैक्सीन के लिए 600 राज्य के माध्यम से और निजी अस्पतालों के लिए 1200 प्रति का निर्णय लिया गया।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसने देश के भीतर महामारी की विस्फोटक दूसरी लहर जिसने दिल्ली, और उत्तर का विनाश का कारण बनी जिसके कारण कई अन्य राज्य सरकारों को सरकार की सहायता लेनने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह प्रशंसनीय है परंतु विरोध में विपक्षी दलों सहित कई अन्य तत्वों ने हमला किया है। जिस पर राजनीति भरपूर देखने को मिली।

जहाँ एक के लिए यह स्वीकारने के कारणों में अच्छे तत्व है कि राज्यों के लिए विकय को खोल दिया गया जिसे अन्य दलों के द्वारा एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में घोषित किया गया। वहीं दूसरी लहर का जिम्मे के लिए राज्य द्वारा केंद्र सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को माना गया तो केंद्र सरकार का यह कहना की की राज्य की सरकारें जानबूझ कर टीके नहीं खरीद रही है। यह दोनों ही विमर्श दर्शातें है कि समस्या जटिल है और ऐसे में इस समस्या से बचने का सबसे अच्छा माध्य है राजनीति का खेला खेला जाए।

जिसकी सहायता से उत्पादन को सक्षमक रने या शीघ्र रोलआउट के लिए पर्याप्त टीकों के विकय का प्रबंधन करने में अपनी विफलता के लिए जवाबदेही से बचना है। जिसके परिणामस्वरूप संघीय संघर्ष को बढ़ते हुए देखा गया है। वही कुछ राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में धन का न होना भी इसका कारण हो सकता है और संघ के विपरित सरलता से पूँजी बाजार का दोहन करने में समर्थता व्यक्त नहीं कर पा रहे। जब चिकित्सकीय ऑक्सीजन के उत्पादन और परिवहन पर बात आती है तब अराजकता के तत्व देखे जाते है। जिसके पीछे यह कहा जा रहा है कि आखिर केंद्र सरकार ने यह किसी भी कारण से होने कैसे दिया।

संघ के लिए सुझाव के रूप में यही बेहतर उपाय है कि वह आवश्यक पड़ने पर अणिक कीमत पर भी टीकों की अपनी खरीद में वद्धि करें और पारदर्शी और सार्वजनिक सूत्र के साथ राज्यों के मध्य अतिरिक्त धन का वितरण किया जाए। और यदि ऐसा नहीं होता दिखता तो इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है। इसका प्रभाव दुर्भाग्यपूर्ण सरकारी नीति को प्रभावित कर रही है।

कई लोगों का तर्क है कि अधिकतर विदेशों में टीकों के लिए एक निजी बाजार अपलब्ध नहीं है, जिसका कारण उन देशों में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। परंतु इस प्रकार के तर्को का भारत में अपनाया बेहद मुश्किल कार्य नजर आ रहा है। जिसमें सर्वप्रथम सरकार के द्वारा किए

गए पूर्व कार्यों से उत्पन्न समस्या है। जिसमें सरकार ने प्रारंभ करने के लिए प्र्यापत भुगतान किया था, या यदि उनके माध्यम से विकय के प्रति प्रतिबद्धताएँ गंभीर थी जो टीका उत्पादकों को आवश्यक रूप से निवेश करने की अनुमति देती थी, तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उपलब्ध अधिक निःशुल्क या सब्सिडी वाले टीकों की कल्पना करना संभव है। परंतु यह बात अब पुरानी हो चुकी है। दूसरी अन्य समस्या यह है कि सरकार के द्वारा निर्मित टीकाकरण क्षमता के पूरक के रूप में एक लाभकारी निजी बाजार विकसित करना भी आवश्यक है। जो कि पहले ही तनाव के दौर से गुजर रहा है। जिसक साथ निजी स्वास्थय देखभाल को सुरक्षा के रूप में साथ आना चाहिए, और यह मात्र बड़े स्तर पर ही ऐसा हो सकता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो एक मानकीकृत परंतु पर्याप्त रूप से लाभदायक मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

तार्किक रूप से इस प्रकार की नीति को बनाए रखना कठिन है क्योंकि वर्तमान स्थिति में निजी उत्पादन स्वयं ही मूल्य निर्धारणकर्ता के रूप में कार्यरत है। इस प्रकार टीकाकरण के माध्यम से राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकारों के मध्य आने वाले भूचाल का कारण निजी बाजार मुख्य भूमिका निभा रहे है जहाँ दामों के निर्धारित होन के उपरांत भी कालाबाजारी को आतंरिक तौर पर देखा जा सकता है वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने चाहे वह केंद्रीय हो या राज्य दोनों ही सरकारें टीकाकरण और स्वास्थय को लेकर विफल रही है। और सफलता की सीढ़ी पर मीडिया ने अपने पंखों को फैलाया है।

कोविड मं जाने वाली जाने और कालाबाजारी जिस पर सरकार की दृष्टि के साथ समाज के लोगों को भी भरपूर सहयोग देने की आवश्यकता थी वहीं अपने चुनावी लक्ष्यों को राजनीतिक दलों ने मुख्य लक्ष्यों में सदैव प्रथम स्थान दिया वहीं दोषारोपण और टीकाकरण के उपरांत जाने वाली कई जानों पर भी लोगों ने जमकर राजनीति करने का प्रयास किया, जिसमें रामदेव जैसे आयुर्वेद के प्रसिद्ध व्यक्ति भी इस पर राजनीति करने से अछूता नही रहे।

इस प्रकार के दाम, कालाबाजारी, मीडिया और और राजनीतिक दल यह तीनों ही तत्व जिस प्रकार से समाज के सामने उभरकर आये वह समाज नागरिकों को या तो संभाल सकता था जिस पर बहुत प्रयास भी हुआ परंतु कुछ दलों के माध्यम से चीजे संभलने से अधिक बिगड़ती हुई दिखी है। जिसने केंद्रीय और राज्य दोनों ही स्तर की राजनीति को प्रभावित कर दोनों में संघर्ष को बनाए रखने का कार्य भरपूर किया है। जबकि उनका कार्य नागरिकों को सहायता अधिक से अधिक पहुँचाने पर होना चाहिए था, सरकार को एक दूसरे के सहयोग के रूप में एक

उदाहरण के रूप में उतरना चाहिए था। जिसमें भूमिका मीडिया ने निाई पर उस भूमिका को और अधिक अच्छा निभाया जा सकता था।

निष्कर्ष

सामान्यतः कहा जा सकता है कि टीकाकरण का सरकारी और निजीकरण होने से होने वाले घाटे में सुधार की उम्मीद की जा सकती है साथ सरकार के माध्यम से आम नागरिक जन को निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराना अपने आप में सराहनीय र्का रहा है। परंतु इस के साथ मानवता कालाबाजारी और राजनीति के रूप से देखने पर शर्मसार होती हुई भी देखी गई है जहाँ मात्र लाभ के उद्धेश्य के लिए नागरिकों के जीवन से खेलना कई परिवारों पर भारी हानि में देखने को मिला है जिसका प्रभाव चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है जिसका कारण कुछ ऐसे निर्णयों का लिया जाना जो इस महामारी के बुरे में कुछ समय के लिए टाल दिए जाने आवश्यक थे। जहाँ टीकाकरण से अधिक आवश्यक राजनीतिक और धार्मिक कार्यो को मान्यता देते हुए संपन्न करते हुए देखा गया। इस प्रकार के कार्यो से बचने की और मीडिया के माध्यम से ऐसे सत्य तथ्यों को समाने लाने की आवश्कता है जिसके माध्म से सरकार और नागरिक दोनो ही सकारात्मक मार्ग का सहारा लें।

♦♦♦♦♦

- संदर्भ–सूची
- https://www.orfonline.org/research/the-politics-of-vaccines/

डी.सी.आर.सी.

# विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली-110007